मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- निकम्मेपन की इन्तहा, डीजी के आदेश भी अनसुने। 3
- सड़कों पर वीआईपी आतंकवाद .....
- पुलिसकर्मी लूटकर खाना अपना अधिकार समझते हैं 4
- बिहार विधानसभा चुनाव : मोदी-नीतीश के लिए अग्निपरीक्षा। 5
- अमितशाह की जेब में सीबीआई- शरद कुमार ने एनआईए भी बिकवाई । 8

वर्ष 28 अंक 18 फरीदाबाद, वीरवार, 16-31 जुलाई 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

राजनीति का भगवा रंग, हिन्दू-मुस्लिम दोनों तंग

प्रशासन सोया रहे तो कानून की कौन कहे

साम्प्रदायिक तनाव का शिकार हुआ अटाली वह गांव है जहां की मुस्लिम आबादी को 1947 में स्वयं हिन्दुओं ने मनुहार करके रोका था। वोटों के ध्रुवीकरण के लिये भगवा राजनीति करने वालों ने गांव में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का बीज गहरा बो दिया है। आये दिन सधियों और अन्य कट्टर हिन्दुत्ववादियों की ओर से कोई न कोई मुद्दा खड़ा करके देश के मुसलमनों को पाकिस्तान भिजवाने की धमकी दी जाती है। परिणामस्वरुप मुसंधियों (मुस्लिम कट्टरवादियों) की ओर से भी साम्प्रदायिक लामबंदी की कवायद जहां-तहां नज़र आती है। अगर वक्त रहते शासक वर्ग न संभला तो पाकिस्तान भेजने की धमकी की जरुरत नहीं रह जायेगी-हिन्दुस्तान के शहर-शहर में पाकिस्तान बना मिलेगा।

मज़दूर मोर्चा, बल्लबगढ़ ब्यूरो

अटाली मामले में जैसे-तैसे एक माह से कुछ अधिक लम्बी खिंची शान्ति 30 जून को यकायक टूट गयी। पुलिस एवं प्रशासन को भरोसा था कि गांव एवं पंचायत के तमाम समझदार लोग आपस में मिल बैठ कर समस्या का समाधान निकाल कर हालात को सामान्य बना लेंगे। परंतु 30 जून को एक धार्मिक स्थल पर कीर्तन करती महिलाओं पर हुई पत्थरबाज़ी की आड़ में गांव में हालात एकदम से बिगाड़ दिये गये। गांव में मौजूद पुलिस बल को और बढा दिया गया। हालात कर्फ़्यू जैसे हो गये। पुलिस ने घर-घर तलाशी लेकर 68 लोग़ों को हिरासत में लेकर उन 9 लोग़ों को गिरफ़्तार कर लिया जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज थे बाकियों को छोड़ दिया। एक को बाद में पकड़ा। अभी 20 और नामजद लोग़ों की तलाश है।

ध्यान रहे कि सभी मुकदमें 25 मई को हुई आग़जनी व हिंसक वारदातों को लेकर अल्पसंख्यकों की ओर से दर्ज कराये गये थे। अल्पसंख्यकों की मांग रही कि जब तक अपराधियों की धर-पकड़ नहीं होगी, वे सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं और शान्ति कैसे बहाल हो सकती है। लेकिन प्रशासन इस प्रयास में था कि ऐसे ही काम चल जाय। अब जो गिरफ़्तार हुए सो हुए बाकी दर्जनों युवक गांव से फ़रार हैं। 20 लोग़ों के विरुद्ध पुलिस ने कोर्ट से गिरफ़्तारी वारंट जारी करा लिये हैं। इनके अलावा दर्जनों पकड़े जाने के भय से फ़रार हैं।

बहुत दिनों तक पंचायतों व तथाकथित अमन कमेटियों की नौटंकी झेलने के बाद अब प्रशासन ने इनकी ओर तवज्जो देना छोड़कर अपने हिसाब से कार्यवाही शुरू कर दी है। इससे अपमानित महसूस करते हुए इन पंचों का एक प्रतिनिधि-मंडल 7 जुलाई को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिला तथा पुलिस ज़्यादती की शिकायत की। विदित है कि केन्द्रीय गृहमंत्री से मिलना इतना सरल नहीं होता। जाहिर है इस मिलन का प्रबन्ध किसी उच्च स्तरीय भाजपाई या संघी नेता ने ही किया होगा। उधर स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय (राज्य) मन्त्री कृष्णपाल अपने (बहुसंख्यक) वोट बैंक को पटाये रखने के लिये सीपी (पुलिस कमिश्नर) सुभाष यादव को इसी माह तक बदलवा दने की कसमें खा रहे हैं। इस तरह की बातों से न केवल शान्ति बहाली की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है बल्कि असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों को बढावा मिलता है। लेकिन मंत्री की चिन्ता अपनी राजनीति चमकाने तक सीमित है।

अटाली का तनाव अभी सुलझा भी नहीं था कि दिनांक 5 जुलाई को थाना सदर पलवल के गांव टीकरी ब्राहम्ण में उत्पाती तत्वों ने एक और उत्पात खड़ा कर दिया। इस बार बहाना था कि पानी भर कर लाती महिला को किसी अल्पसंख्यक ने छेड़ दिया। बस फ़िर क्या था। दोनों तरफ़ से न केवल लाठी, बल्लम व तलवार आदि बल्कि बन्दूकें तक निकल आईं। दोनों ओर के दर्जनों लोग घायल हो गये। मौके पर तुर्त-फुर्त पहुंची पुलिस के भी कुछ लोग इस झगड़े में घायल हो गये। पुलिस ने दोनों ओर की तरफ़ से मुकदमें दर्ज करने के अलावा अपनी तरफ़ से भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तथा पुलिस पर हमला करने का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों पक्षों से गिरफ़्तारियां भी कर लीं। कुछ घायल खबर लिखे जाने तक अस्पताल में भर्ती थे।

सवाल समझने वाला यह है कि यदि किसी महिला को किसी ने वास्तव में छेड़ा भी हो तो इस तरह का साम्प्रदायिक उपद्रव करने का क्या मतलब? बाकायदा कड़ा कानून है, जिसके तहत त्वरित कार्यवाही कराई जा सकती थी। दूसरा सवाल समझने वाला यह है कि महिला को छेड़ने के नाम पर सशस्त्र युद्ध पर उतारू लोग उस वक्त कहां होते हैं जब उन्हीं के सम्प्रदाय के दहेज-लोभी महिला को जिंदा जला देते हैं या पुत्र की चाह में गर्भ में ही लड़की को जन्म लेने से पहले मार डालते हैं?

दरअसल दंगा भड़काने वालों को न महिला से कुछ मतलब होता है न किसी धार्मिक स्थल से। उन्हें तो तनाव पैदा करनेवाले किसी बहाने की तलाश रहती है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार टीकरी ब्राह्मण दंगे का लाभ उठा कर पड़ोसी गांव फुलवाड़ी के गूजर दंगा पीड़ित मेवों की 18 भैंसे खोल कर ले गये। इसके अलावा पीड़ितों के घरों से जो लूट-पाट हुई वह अलग। दंगे को और हवा देने के लिये उसी दिन पलवल शहर में संघ परिवार के संगठनों-राम सेना व बजरंग दल आदि ने प्रदर्शन व नारेबाज़ी भी की।

बिगड़े माहौल से प्रेरित होकर पलवल के ही थाना बहीन के अन्तर्गत गांव अंधोप में भी 7 जुलाई को दंगा भड़का। यहां पर बहाना बनाया गया एक सांड पर तथाकथित क्रूरता को। दंगाइयों का आरोप था कि कुछ अल्पसंख्यकों ने एक सांड पर लाठियों व बल्लमों से घातक प्रहार किये। दूसरे पक्ष का कहना है कि सांड ने उनके खेत में खड़ी जवार की फ़सल उजाड़ दी। उसे खेत से बाहर निकालना आसान नहीं होता। अकेले-दुकेले आदमी पर तो वह घातक हमला भी कर सकता है। ऐसे में कई लोग मिल कर उसे लाठी बल्लम आदि से भगाते हैं। लेकिन यहां आरोप यह भी है कि खेत से निकालने के बाद भी सांड पर हमला जारी रहा।

शेष पेज 2 पर

ये देखिये, मोदी के गुरूजी के विचार.....

"हिन्दुओ, ब्रिटिश से लडने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अपनी ताकत हमारे भीतरी दुश्मनों यानि मुसलमानों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों से लडने के लिए बचाकर रखो।"

- एम.एल. गोलवरकर आर.एस.एस के दूसरे सरसंघचालक

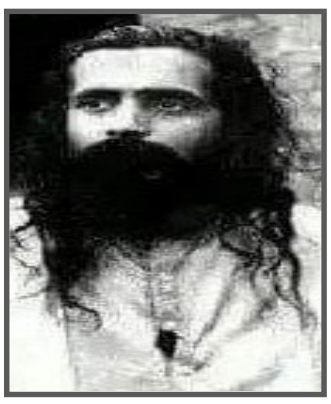

ख़बर दार

'ईमानदार' केजरी हो रहा तार-तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ईमानदार प्रशासन के मुद्दे पर जनता का अभूतपूर्व विश्वास जीतने में सफ़ल हुए थे। पर एक-एक करके उनकी पार्टी के प्रमुख नाम भ्रष्टाचार और जालसाज़ी के आरोपों से घिरते नज़र आ रहे हैं। विडम्बना यह है कि ईमानदारी की लड़ाई के अगवा योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण को पार्टी से धकिया कर बाहर करने वाली केजरीवाल मंडली अपने भ्रष्ट सहयोगियों का अन्तिम समय तक निहायत बेशर्मी से बचाव कर रही है। यहां तक कि केजरीवाल की बहुप्रचारित भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ाई भी महज प्रचारात्मक रह गयी है। इस बार का काल्पनिक साक्षात्कार इन्हीं आयामों को लेकर।

म.मो.-आपने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये क्या किया है? विशेषकर जब आपके अपने मन्त्रियों व विधायकों के खिलाफ़ नित नये-नये मामले सामने आ रहे हैं।

केजरीवाल-हमने तो सोचा था कि 35 कर्मचारियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार का मसला हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। पर यहां तो, लगता है, जल्द ही दिल्ली पुलिस ही हमारे 35 विधायकों को भ्रष्टाचार में बन्द करके हिसाब बराबर कर देगी। यह भी भरोसा मुझे नहीं रहा कि मनीष सिसोदिया भी कितने दिन बचा रह पायेगा।

म.मो.-आखिर आप अपने भ्रष्ट सहयोगियों को अपने से दूर क्यों नहीं कर देते? क्या उनके बने रहने से आपकी छवि खराब नहीं हो रही?

केजरीवाल-सवाल मेरी या पार्टी का उतना नहीं रह गया है। अब तो मेरे लिये विधायक ही सर्वोपरि हैं। याद नहीं मैंने यादव और भूषण से भी कह दिया था कि तुम पार्टी संभालो, मैं अपने विधायकों को लेकर अलग हो जाता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मेरे लिये विधायकों से प्यारा और कौन हो सकता है?

म.मो.-दिल्ली के लोग़ों ने आप को 70 में से 67 विधायक दिये। फ़िर आपको 500 करोड़ से ऊपर अपनी छवि चमकाने में खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गयी? सत्तारूढ होने के बाद तो आपका काम बोलेगास न कि विज्ञापनबाज़ी।

केजरीवाल-अरे भई यह सिर्फ़ छवि का सवाल नहीं है। अपने चहेते मीडिया वालों और विज्ञापन एजेंसी वालों का भी तो ख्याल रखना है। फ़िर मनीष सिसोदिया के घर की विज्ञापन एजेंसी को ही तो इसमें से अधिकांश रकम जा रही है। यह रकम घूम-फ़िर कर हमारे काम ही तो आयेगी।

म.मो.-कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तारूढ होने के बाद आपने भी ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया हो। लोग़ों को आपसे बहुत आशायें हैं और यदि आपके दामन पर बेईमानी के छींटे दिखे तो सभी को घोर निराशा होगी।

केजरीवाल-नहीं,नहीं। मैं किसी को ये छींटे देखने नहीं दूंगा। देखते नहीं, मैंने ईमानदारी का लबादा इतना कस कर ओढ रखा है। अपने तमाम सहयोगियों को भी मेरा यही संदेश है कि करो चाहे कुछ भी पर ईमानदारी का लबादा जरूर ओढे रखना। सच्चाई यह है कि उनमें से कई तो इस कला में मुझसे भी अधिक माहिर हैं।

म.मो.-क्या आप देश की जनता के लिये व अपने गुरू अन्ना हज़ारे के लिये कोई संदेश देना चाहेंगे? विशेषकर, लोकपाल के मुद्दे पर।

केजरीवाल-अन्ना जी के लिये तो हमारा संदेश काफ़ी दिनों से स्पष्ट है-जैसे सभी आपका साथ छोड़ गये, हम भी छोड़ चुके हैं। अब आप अपने गांव में बैठकर बयानबाज़ी करते रहिये, दिल्ली में लोकपाल की राजनीति अब हमने पूरी तरह सम्भाल ली है। जनता से हमारा संदेश है कि जब हमने आन्तरिक लोकपाल को ही जीरो कर दिया तो क्या किसी और लोकपाल का हश्र बताने की जरूरत बची है?

मोदी की कही मनोहर ने मानी: 'न खाऊंगा' की ठानी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुयायी उनकी तारीफ़ में और कुछ भले न कह पाते हों पर इतना दावा तो कर ही देते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी के 'न खाऊंगा' के सिद्धान्त का अक्षरश: पालन करते हैं। रही बात मोदी-सिद्धांत दूसरे भाग यानी 'न खाने दूंगा' की तो उस पर तो स्वयं मोदी भी अमल नहीं कर पा रहे। फ़िर भला बेचारे मनोहर की क्या बिसात।

मोदी और मनोहर दोनों के सामने समस्यायें एक जैसी हैं। न सिर्फ़ उन्हें सत्ता चलानी है बल्कि कार्पोरेट और संघ का मतलब साधने वाली ही चलानी है। कार्पोरेट का मुंह तो सुरसा की तरह खुलता ही जाता है, यह अब मोदी-मनोहर से छिपा नहीं। संघियों ने भी डकार लेनी बंद कर दी है, यह मोदी की जानकारी में तो होगा ही क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री गुजरात उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का अनुभव था। पर हो सकता है संघ के पैदल खिलाड़ी मनोहर लाल के लिये यह नया अनुभव है।

हरियाणा के राजनीतिक परिदृष्य पर नज़र रखनेवालों को शुरू में आश्चर्य हुआ कि मनोहर सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के आर्थिक घोटालों से आंख मूंदे रखी है। धीरे-धीरे अब सभी को यकीन होता जा रहा है कि तमाम पुराने लूट-खसूट के धंधे सरकारी फ़ाइलों में दफ़न कर दिये जायेंगे। ऐसा इसलिये नहीं कि मनोहर लाल की हुड्डों या चौटालों से कोई दोस्ती निकल आई हो। इसका एकमात्र कारण यही नज़र आता है कि शासन और प्रशासन के वही पुराने भ्रष्ट तेवर आज भी बरकरार हैं, ऐसे में किसकी जांच करायें और किससे करायें? कल को जब मनोहर सरकार भी नहीं रहेगी तो वे भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जांच हो। मनोहर लाल से ज़्यादा यह रवैया उनके वरिष्ठ मन्त्रियों को रास आता है।

लिहाज़ा मनोहर ने मोदी की मानी तो सही पर आधी से ज़्यादा नहीं। मोदी भी उनसे क्या सवाल-जवाब करेंगे। आखिर वे भी तो 'न खाने दूंगा' को लेकर पूरी तरह असफ़ल सिद्ध हो रहे हैं।